दैनिक
# न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

**आवश्यक सूचना**

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शुक्रवार 29 जुलाई 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-04, अंक- 301

## महत्वपूर्ण एवं खास

### रांची एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, सीआईएसएफ जवानों ने संभाला मोर्चा

**रांची (आरएनएस)।** झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि फोन पर रांची एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सीआईएसएफ के जवानों ने सर्च अभियान शुरू कर दिया है। वहीं धमकी के बाद रांची एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सूत्रों के अनुसार फोन पर रांची एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सीआईएसएफ के जवानों ने सर्च अभियान शुरू कर दिया है। इसके साथ ही रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर चप्पे-चप्पे की तलाशी जारी है। इस मामले पर रांची एयरपोर्ट निदेशक केएल अग्रवाल ने धमकी मिलने की खबर की पुष्टि की है। केएल अग्रवाल ने बताया कि धमकी का कॉल आया था, लेकिन, जांच के बाद ये कॉल होक्स कॉल निकला। धमकी भरे कॉल के बाद एयरपोर्ट एरिया में सर्च अभियान चलाया गया है।

### तमिलनाडु में कूडनकुलम बिजली संयंत्र के कारण कोई विस्थापन नहीं हुआ : केंद्र सरकार

**नईदिल्ली (आरएनएस)।** केंद्र सरकार ने कहा है कि तमिलनाडु में कूडनकुलम बिजली संयंत्र के कारण कोई विस्थापन नहीं हुआ है। राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार); अर्थ विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने जमीन-जायदाद के बारे में जो मुआवजा तय किया था, वह भू-स्वामियों को चुका दिया गया था। इस बहाली प्रक्रिया के जरिये 72 परियोजनाओं से पीड़ित होने वाले व्यक्तियों को अब तक नौकरी दी जा चुकी है। ठेकेदारों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को भी रोजगार दिया गया है। इसके अलावा, सामान और सेवाओं की आपूर्ति करने को स्थानीय लोगों के लिये अवसर भी पैदा किये गये हैं। जो परियोजना स्थापित की गई, उसने एनपीसीआईएल में स्थानीय लोगों के लिये रोजगार के अवसर पैदा किये हैं। विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार केकेएनपीपी में समूह 'सी' के पदों पर 72 परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों की बहाली में आयु और अंक-प्रतिशत की आवश्यक योग्यता में भी ढील दी गई है।

### केदारनाथ हाईवे मलबा आने से आठ घंटे बंद रहा

**रुद्रप्रयाग (आरएनएस)।** रुद्रप्रयाग-गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग तिलवाड़ा और रामपुर के बीच मलबा आने के कारण आठ घंटे बंद रहा। इस दौरान तीर्थयात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। काफी प्रयासों के बाद एनएच द्वारा दोपहर 2 बजे हाईवे आवाजाही के लिए सुचारु किया गया। बीती रात से हो रही बारिश के कारण गुरुवार सुबह 6 बजे रुद्रप्रयाग-गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग रामपुर के पास पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आने के कारण बंद हो गया। इस बीच अच्छी बात यह रही कि मलबा आते हुए कोई वाहन यहां से आवाजाही नहीं कर रहा था। हाईवे बंद होने के कारण केदारनाथ की ओर से रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग की ओर से केदारनाथ जाने वाले वाहनों को जाम में फंसना पड़ा है। कई स्थानीय लोगों ने पहाड़ी से चढ़ते हुए इस स्थान को पार किया किंतु हाईवे के दोनों ओर वाहन फंसे रहे। इधर, तिलवाड़ा और अगस्त्यमुनि क्षेत्र से रुद्रप्रयाग आने वाले स्थानीय लोगों को ज्यादा दिक्कतें उठानी पड़ी जो नियमित आवाजाही करते हैं। वहीं कई जरूरी सामान की आपूर्ति भी दोपहर दो बजे बाद हुई। दो बजे बाद हाईवे को वाहनों की आवाजाही के लिए सुचारु कर दिया गया।

### कुछ निलंबित सदस्य संसद परिसर में गांधी की प्रतिमा के समक्ष पूरी रात मौजूद रहे

**नई दिल्ली(आरएनएस)।** विपक्ष के कुछ निलंबित सदस्य अपने खिलाफ हुई कार्रवाई के विरोध में संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष बुधवार की पूरी रात मौजद रहे। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन और कुछ अन्य सदस्यों ने रात के समय धरना दिया। निलंबित विपक्षी सदस्य अपने निलंबन के खिलाफ बुधवार से 50 घंटे का धरना दे रहे हैं। उच्च सदन में मंगलवार को अशोभनीय आचरण के लिए लोकसभा में चार कांग्रेस सदस्यों को मानसून सत्र की शेष अवधि और राज्यसभा के 20 विपक्षी सदस्यों को वर्तमान सप्ताह के शेष समय के लिए निलंबित किया गया है।

# छत्तीसगढ़ बना गौ-मूत्र खरीदी करने वाला देश का पहला राज्य

- मुख्यमंत्री ने हरेली पर्व से राज्य में गौ-मूत्र खरीदी का किया शुभारंभ
- मुख्यमंत्री गौ-मूत्र विक्रय कर बने प्रथम विक्रेता
- छत्तीसगढ़ में जैविक खेती को बढ़ावा देने एक और पहल
- गौठानों में जैविक खाद के साथ-साथ अब जैविक कीटनाशक का होगा उत्पादन

**रायपुर/नई दिल्ली (आरएनएस)।** मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में धूम-धाम से आयोजित हरेली पर्व के अवसर पर राज्य में गौ-मूत्र की खरीदी की ऐतिहासिक की शुरूआत की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर चंदखुरी की निधि स्व-सहायता समूह को 5 लीटर गौ-मूत्र 20 रूपए में बेचकर राज्य के पहले विक्रेता बने। निधि स्व-सहायता समूह ने गौ-मूत्र विक्रय की यह राशि भूपेश बघेल के आग्रह पर मुख्यमंत्री सहायता कोष के खाते में जमा की। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जो पशुपालक ग्रामीणों से दो रूपए किलो में गोबर खरीदी के बाद अब 4 रूपए लीटर में गौ-मूत्र की खरीदी कर रहा है।

मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में धूमधाम से आयोजित हरेली पर्व के मौके पर मुख्यमंत्री ने कृषि यंत्रों की पूजा की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने गौ-माता को चारा खिलाया और उसकी पूजा की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राज्य के जैविक खाद उत्पादक 7442 महिला स्व-सहायता समूहों को 17 करोड़ रूपए की प्रोत्साहन (बोनस) राशि का भी वितरण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा कि गोधन न्याय योजना के बहुआयामी परिणामों को देखते हुए देश के अनेक राज्य इसको अपनाने लगे हैं। इस योजना के तहत अमीर हो या गरीब सभी दो रूपए किलो में गौठानों में गोबर बेच रहे हैं। बीते दो सालों में गोधन न्याय योजना के माध्यम से गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों और महिला समूहों के खाते में 300 करोड़ रूपए से अधिक की राशि अंतरित हुई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेती-किसानी समृद्ध हो, किसान खुशहाल हो यह हमारी कोशिश है। जैविक

खाद और जैविक कीटनाशक का खेती में उपयोग करने से खेती की लागत में कमी आएगी। खाद्यान्न की गुणवत्ता बेहतर होगी, जिससे जन-जीवन का स्वास्थ्य बेहतर होगा।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार देश की इकलौती सरकार है, जो अपने राज्य के पशुपालक ग्रामीणों से बीते दो सालों से गोबर खरीद रही है। आज 28 जुलाई को हरेली पर्व से छत्तीसगढ़ में गौ-मूत्र की सरकारी खरीदी की विधिवत शुरूआत हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की यह पहल वास्तव में राज्य में पशुपालन के संरक्षण और संवर्धन के साथ-साथ पशुपालक की आय और जैविक खेती को बढ़ावा देना है। राज्य में बीते दो सालों से गोबर की खरीदी और इससे जैविक खाद के निर्माण से राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिला है। गौ-मूत्र खरीदी का मकसद गौठानों में इससे जैविक कीटनाशक, जीवामृत, ग्रोथ प्रमोटर का निर्माण

करना है, ताकि राज्य के किसानों को कम कीमत पर जैविक कीटनाशक सहजता से उपलब्ध कराया जा सके। यहां यह उल्लेखनीय है कि गोधन न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में आज से 2 साल पहले 20 जुलाई 2020 को हरेली पर्व के दिन से हुई थी। इसके तहत गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों से 2 रुपये किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। देश-दुनिया में गोबर की खरीदी की गोधन न्याय योजना की बेजोड़ सफलता ही गौ-मूत्र की खरीदी का आधार बनी है। गोबर खरीदी के जरिए बड़े पैमाने पर जैविक खाद का निर्माण और उसके उपयोग के उत्साहजनक परिणामों को देखते हुए अब गोमूत्र की खरीदी कर इससे कीट नियंत्रक उत्पाद, जीवामृत, ग्रोथ प्रमोटर बनाए जाएंगे। इसके पीछे मकसद यह भी है कि खाद्यान्न उत्पादन की विषाक्तता को कम करने के साथ ही खेती की लागत को भी कम किया जा सके। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित हरेली पर्व के कार्यक्रम में मंत्रियों सहित बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे।

## भारतीय नौसेना की बढ़ी ताकत, हेलफायर मिसाइल से लैस समंदर में शिकार करेगा 'रोमियो'

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** आज अमेरिका के मल्टी रोल हेलिकॉप्टर 'रोमियो' भारत पहुंच गए हैं। नौसेना में शामिल किए जाने के लिए कोच्चि शिपयार्ड ने दोनों रोमिया को सौंपा। ये हेलिकॉप्टर भारतीय नौसेना की क्षमता में इजाफा करेंगे। ये इतने पावरफुल हैं कि रोमियो हेलिकॉप्टर से किसी जहाज पर हमला आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा इनका इस्तेमाल राहत और बचाव कार्य में भी किया जा सकता है। इतना ही नहीं इसके जरिए हवा से सतह पर मार करने वाली हेलफायर मिसाइलें दागी जा सकती है।

भारतीय नौसेना के मुताबिक, तीसरा रोमिया हेलीकॉप्टर भी अगले महीने भारत पहुंच जाएगा। जबकि सभी 24 रोमियो हेलीकॉप्टर 2025 तक भारतीय नौसेना को मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि इन हेलिकॉप्टर्स के लिए भारत ने अमेरिका से करार किया है। बताया जा रहा है कि हेलिकॉप्टर की तैनाती इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पर होगी। इस हेलिकॉप्टर के जरिए सबमरीन को ढूंढ कर तबाह किया जा सकता है, साथ ही समंदर में निगरानी रखी जा सकती है।

## देश में मिले कोरोना के 20557 नए मरीज, 45 लोगों की मौत

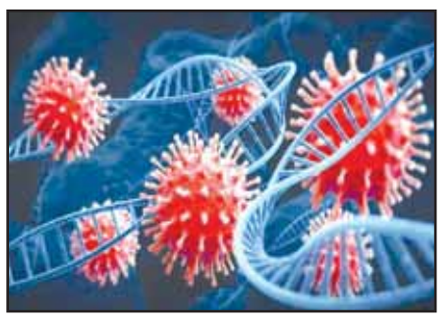

**नईदिल्ली (आरएनएस)।** भारत में बीते दिन कोरोना वायरस से संक्रमण के 20,557 नए मामले सामने आए और 45 लोगों की मौत हुई। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,39,59,321 हो गई है। इनमें से 5,26,212 मरीजों की मौत हुई है। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,46,322 हो गई है। एक दिन पहले देश में 18,313 नए मामले दर्ज हुए थे। तीन दिनों बाद देश में दैनिक मामलों की संख्या 20,000 से ऊपर गई है।

कोरोना वायरस के संक्रमण को हराकर ठीक होने वालों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देशभर में 19,216 मरीज ठीक हुए। इसी के साथ महामारी को हराकर ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या 4,32,86,787 हो गई है। देश की रिकवरी रेट 98.47 प्रतिशत है। कोरोना टेस्ट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देशभर में 3,96,783 टेस्ट किए गए हैं। अब तक देश में लगभग 87.40 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं।

सबसे अधिक प्रभावित राज्यों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में अब तक 80,39,319 लोगों को संक्रमित पाया जा चुका है और 1,48,088 लोगों की मौत हुई है। दूसरे सर्वाधिक प्रभावित राज्य केरल में रविवार तक 67,10,792 लोगों को संक्रमित पाया जा चुका था और 70,394 मरीजों की मौत हुई है। 35,37,895 मामलों और 38,032 मौतों के साथ तमिलनाडु और 39,99,766 मामलों और 40,094 मौतों के साथ कर्नाटक और अगले दो सबसे अधिक प्रभावित राज्य हैं।

सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल में ही नए मामले भी सबसे अधिक आ रहे हैं। महाराष्ट्र में दैनिक मामलों में फिर उछाल देखा गया है और बीते दिन यहां 2,138 नए मामले सामने आए। इसी तरह तमिलनाडु में बीते दिन 1,803 नए मामले पकड़ में आए, वहीं केरल में रविवार को 1,700 नए लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था। कर्नाटक में बीते दिन 1,624 नए मामले सामने आए।

वैक्सीनेशन अभियान की बात करें तो देश में अब तक वैक्सीन की 2,03,21,82,347 खुराकें लगाई जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, बीते दिन 40,69,241 खुराकें लगाई गईं। देश में 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों और वयस्कों को वैक्सीन लगाई जा रही है।

## राष्ट्रपति के खिलाफ विवादित टिप्पणी पर महिला आयोग ने अधीर रंजन चौधरी को किया तलब, 3 अगस्त को पेशी

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** राष्ट्रपत्नी वाले बयान को लेकर सदन से सडक़ पर हंगामा बरपा हुआ है। अब राष्ट्रीय महिला आयोग भी इस विवाद में सामने आई है। गुरुवार को आयोग ने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को नोटिस जारी कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए स्पष्टीकरण मांगा। महिला पैनल ने कांग्रेस नेता से व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। इस संबंध में सुनवाई 3 अगस्त को सुबह 11.30 बजे होनी है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने पश्चिम बंगाल से कांग्रेसी सांसद अधीर रंजन चौधरी के बयान को आड़े हाथों लिया है। अधीर रंजन ने संसद में अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रपति दौपदी मुर्मू के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया था। भाजपा सांसदों के मुताबिक, अधीर रंजन ने जानबूझकर दो बार इस शब्द का इस्तेमाल किया। जबकि कांग्रेस पार्टी इसे अधीर रंजन की अनजाने में की गई भूल बता रही है।

हालांकि अपने बयान पर अफसोस जताते हुए अधीर रंजन ने कहा कि वो राष्ट्रपति से व्यक्तिगत तौर पर माफी मांगेंगे। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी इस मामले में हस्तक्षेप करने और चौधरी के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा था।

**महिला आयोग ने किया तलब**

अब अधीर रंजन चौधरी के विवादित बयान को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग सामने आया है। अधीर रंजन के बयान का संज्ञान लेते हुए आयोग ने उन्हें आगामी 3 अगस्त को पेश होने के लिए कहा है। अधीर रंजन से मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है और कहा है कि वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे। इस संबंध में आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से चौधरी के खिलाफ उचित ऐक्शन लेने के लिए खत लिखा है।

## अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर से 6 किलो सोना और 28 करोड़ रुपये की नकदी मिली

**कोलकाता (आरएनएस)।** प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अर्पिता मुखर्जी से संबद्ध एक अपार्टमेंट से 6 किलो सोना और 27.9 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की है। मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के गिरफ्तार किए गए मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी सहयोगी माना जाता है। अधिकारियों ने गुरुवार सुबह बताया कि बुधवार को बेलघरिया में एक अपार्टमेंट से नकदी बरामद की गयी और रातभर गिनती करने के बाद 27.90 करोड़ रुपये पाए गए। उन्होंने बताया कि जांचकर्ता सोने के आभूषण की कीमत का पता लगा रहे हैं। जांच एजेंसी ने पांच दिन पहले दक्षिण कोलकाता के टॉलीगंज इलाके में मुखर्जी के एक अन्य फ्लैट से आभूषण और विदेशी मुद्रा के अलावा 21 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी बरामद की थी। अधिकारियों ने बताया कि कुल मिलाकर अभी तक 50 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की गयी है। ईडी अधिकारियों ने बुधवार को दक्षिण कोलकाता के राजदांगा और उत्तरी कोलकाता के बेलघरिया में विभिन्न ठिकानों पर छापे मारे थे। अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ के दौरान मुखर्जी ने ईडी को इन संपत्तियों की जानकारी दी है। ईडी अधिकारियों को बेलघरिया के रथतला इलाके में दो फ्लैट्स में घुसने के लिए दरवाजा तोडऩा पड़ा, क्योंकि उनकी चाभियां नहीं मिली थी। अधिकारी ने बताया कि तलाशी के दौरान फ्लैट्स से कई 'अहम' दस्तावेज भी बरामद किए गए। ममता बनर्जी की सरकार में प्रभावशाली मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें अर्पिता मुखर्जी के टॉलीगंज फ्लैट में नकदी मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया।

## सत्रह वर्ष से अधिक आयु के युवा पहले से ही मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने कर सकते हैं आवेदन : निर्वाचन आयोग

**नईदिल्ली (आरएनएस)।** 17+ वर्ष के युवा अब मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें किसी वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्वापेक्षित मानदंड की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पाण्डेय के नेतृत्व में भारतनिर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ)/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ)/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एईआरओ) को इस तरह के प्रौद्योगिकी-सक्षम समाधान तैयार करने के निर्देश दिए हैं कि युवाओं को न केवल 1 जनवरी को बल्कि तीन पश्चातवर्ती अर्हक तिथियों अर्थात 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर के संदर्भ में भी अपने अग्रिम आवेदन दाखिल करने की सुविधा मिल सके। अब से, निर्वाचक नामावली प्रत्येक तिमाही में अद्यतन की जाएगीऔर पात्र युवाओं को उस वर्ष की अगली तिमाही में पंजीकृत किया जा सकता है जिसमें उन्होंने 18 वर्ष की पात्रता आयु पूरी कर ली हो। पंजीकरण करवाने के बाद उन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) जारी किया जाएगा। निर्वाचक नामावली, 2023 के वार्षिक पुनरीक्षण के चालू राउंड के लिएवर्ष 2023 के 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला कोई भी नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन की तारीख से अग्रिम आवेदन जमा कर सकता है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 14(ख) में विधिक संशोधनों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 में किए गए परिणामी संशोधनों के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली को तैयार करने/उसका पुनरीक्षण करने के लिए आवश्यक परिवर्तन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्मरण रहे कि भारत निर्वाचन आयोग की अनुशंसापर, विधि एवं न्याय मंत्रालय ने हाल ही में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया है, जिसमें निर्वाचक नामावलियों में युवाओं के लिए पंजीकृत होने की पात्रता के लिए केवल 01 जनवरी की पूर्ववर्ती सिर्फ एक अर्हक तिथि की पुरानी व्यवस्था के उलटचार अर्हक तिथियों अर्थात 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्तूबर का उपबंध किया गया है।

मौजूदा नीति के अनुसार, अर्हक तिथि के रूप में आने वाले वर्ष की पहली जनवरी के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षणसामान्यतया सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष के उत्तरवर्ती भाग में (सामान्यत: वर्ष की अंतिम तिमाही में) किया जाता था ताकि निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन उत्तरवर्ती वर्ष की जनवरी के प्रथम सप्ताह में किया जा सके। इसका अर्थ यह हुआ कि 1 जनवरी के बाद बड़ी संख्या में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को नामांकन के लिए अगले वर्ष के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी और वे बीच की अवधि में हुए चुनावों में भाग लेने में सक्षम नहीं हो पाते थे।

आयोग ने पंजीकरण प्ररूपों को भी प्रयोक्ता के लिए और अधिक अनुकूल तथा सरल बना दिया है। नव- आशोधित प्ररूप1 अगस्त, 2022 से लागू होंगे। 01 अगस्त, 2022 से पहले पुराने प्ररूपों में प्राप्त सभी आवेदनों (दावे और आपत्तियां) पर कार्रवाई की जाएगी और इनका निस्तारण किया जाएगा तथा ऐसे मामलों में नए प्ररूपों में आवेदन दाखिल करने की जरूरत नहीं है।

आयोग ने मतदान होने वाले राज्यों को छोडक़र बाकी सभी राज्यों में अर्हक तिथि के रूप में 01.01.2023 के संदर्भ में वार्षिक संक्षिप्त पुनरीक्षण का आदेश दिया है। पुनरीक्षण-पूर्व सभी गतिविधियां आयोग के मौजूदा अनुदेशों और दिशानिर्देशों तथा निर्वाचक नामावली मैनुअल, 2016 और मतदान केंद्रमैनुअल, 2020 के अनुसार की जाती हैं। पुनरीक्षण और पुनरीक्षण-पूर्व गतिविधियां इस तरह से की जाती हैं किनिर्वाचक नामावलियां अंतिम रूप से राष्ट्रीय मतदाता दिवस (प्रत्येक वर्ष की 25 जनवरी) से काफी पहले प्रकाशित की जा सकें ताकि नए निर्वाचकों विशेषकर युवा मतदाताओं (18-19 वर्ष) के लिए तैयार एपिक राष्ट्रीय मतदाता दिवस (एनवीडी) के अवसर पर समारोह में उन्हें वितरित किए जा सकें।